आर.एन.आर.

सुनीता रानी, -पेटिशनर

बनाम
हरियाणा और अन्य राज्य, उत्तरदाता

1998 का CWP नंबर 16584

1 सितंबर, 2010

आयोजित, कि यह अदालत इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती है कि यह अखबार में रिपोर्ट के प्रकाशन के कारण था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी और उसके बाद उस जांच के आधार पर, उसकी सेवाओं के साथ भेज दिया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता की सेवाएं उसके हिस्से पर असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण नहीं बल्कि ओवरट कृत्यों के कारण, जो कदाचार की राशि थी, के कारण नहीं किया गया है। यदि ऐसा है, तो नियोक्ता के लिए याचिकाकर्ता को सुनने का अवसर देना अनिवार्य था। इसलिए, याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति का क्रम सहज लग सकता है लेकिन इसके प्रभाव और पदार्थ के लिए समान, प्रकृति में कलंक है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को यह दिखाने के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए कि क्या उसने छात्र पर कथित सजा दी है या नहीं। इसलिए, इस मामले में एक नियमित जांच की जानी चाहिए थी और याचिकाकर्ता, एक तदर्थ कर्मचारी, को खुद का बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

(पारस 19 और 20)

याचिकाकर्ता के लिए कोहल शर्मा, एडवोकेट के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आर। के। मलिक।

हिमांशु राज, सहायक अधिवक्ता जनरल, मैं हरियाणा, राज्य के लिए।

याचिकाकर्ता, एक विज्ञान शिक्षक, ने छात्रों को दंडित किया, जिसके

परिणामस्वरूप 14 अक्टूबर 1998 के आदेश के तहत उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इन दोनों आदेशों को इस आधार पर हमला किया गया है कि वे प्रकृति में कलंक हैं और याचिकाकर्ता की सेवाओं को एक तदर्थ नियुक्त करने के बावजूद भी नहीं किया जा सकता है।

(२) इसलिए, इस न्यायालय को यह निर्धारित करना होगा कि क्या समाप्ति के आदेशों में कोई भी प्रतिरूपण या कदाचार शामिल है, जिसका याचिकाकर्ता के भविष्य के रोजगार पर असर हो सकता है, या नहीं, और यदि ऐसा है। जैसा कि एक नियमित जांच की जानी थी या नहीं। आगे। याचिकाकर्ता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में खुद का बचाव करने के अवसर से वंचित किया जा सकता है, इस अदालत द्वारा भी निर्धारित किया जाना है।
(३) इन सवालों के जवाब देने के लिए, मामले के तथ्यों को नोटिस करना आवश्यक होगा।
(४) याचिकाकर्ता गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कैथल में तदर्थ आधार पर एक विज्ञान शिक्षक के रूप में शामिल हुए, (इसके बाद, 'स्कूल') को नियुक्ति पत्र के अनुसरण में संदर्भित किया गया (अनुलग्नक पी -1) 27 नवंबर, 1995 को दिनांकित । नियुक्ति पत्र में निम्नलिखित शामिल थे

शब्द, जिन्हें वर्तमान मामले के स्थगित करने के लिए देखा जाना आवश्यक है:
"निम्नलिखित उम्मीदवारों को स्कूल में तदर्थ आधार पर 1400/2600 रुपये के पे-स्केल में नियुक्त किया जाता है, जो 24 मई, 1996 तक और गर्मियों की छुट्टियों तक उनके नाम के खिलाफ नोट किया गया है। उनकी सेवाओं को किसी भी समय बिना किसी समय समाप्त किया जा सकता है। नोटिस या हरियाणा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार में शामिल होने पर जो भी पहले हो। वे नियुक्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपने कर्तव्यों में शामिल हो सकते हैं अन्यथा उनकी नियुक्ति को रद्द करने के लिए माना जाएगा। "

(५) याचिकाकर्ता ने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। 24 अगस्त, 1998 को, वह कक्षा 10, खंड 'ई' के छात्रों को पढ़ा रही थी और यह चौथी अवधि थी। कुछ छात्रों, जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था,

को याचिकाकर्ता द्वारा स्कूल के वॉलीबॉल कोर्ट के एक दौर में लेने के लिए दंडित किया गया था। एक छात्र, अर्थात् कुमारी सपना, थकान और सजा को सहन करने में सक्षम नहीं था, बेहोश हो गया और उसे सरकारी अस्पताल, कैथल में ले जाया गया, जहां डॉ। डी। सी। थुकराल, चिकित्सा अधिकारी ने उसका इलाज किया। 9 सितंबर, 1995 को डॉक्टर द्वारा जारी की गई मेडिको-कानूनी रिपोर्ट, यानी घटना के 15 दिनों की अवधि के बाद, वर्तमान याचिका के साथ एनेक्स्योर पी -6 के रूप में एनेक्स किया गया है और उसी के रूप में पढ़ता है:-

"रिकॉर्ड्स के अनुसार, बच्चे को चोट का कोई बाहरी निशान नहीं था। उसे 26 अगस्त, 1998 से 28 अगस्त, 1998 तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, -वाइड सी। आर। नंबर 4481. वह सांस के कारण के लक्षण और चेतना के नुकसान के लक्षण थे। कुछ मिनटों के लिए और हिस्टीरिया (कार्यात्मक विकार) के मामले के रूप में निदान किया गया था और इसे रूढ़िवादी लाइनों पर इलाज किया गया था। यह बीमारी बच्चे के दिमाग में मनोवैज्ञानिक तनाव या संघर्ष के कारण है।
9 सितंबर, 1998।

(६) एक दैनिक हिंदी अखबार 'पंजाब केसरी' ने 27 अगस्त, 1998 को अपने प्रकाशन में एक खबर दी कि स्कूल ऑफ याचिकाकर्ता का एक छात्र दो दिनों तक बेहोश रहा, क्योंकि कॉर्पोरल सजा उस पर भड़काई हुई थी। समाचार के प्रकाशन के बाद, एक प्रारंभिक जांच आदेश दिया गया था और याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा एक प्रश्नावली (अनुलग्नक पी -3) दिया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रश्नावली को भर दिया और इसे जांच अधिकारी को सौंप दिया। प्रश्न संख्या 4 और उत्तर के रूप में पढ़ें--
"4. क्या आपने 24 अगस्त, 1998 को उपर्युक्त छात्र को दंडित किया है? यदि हाँ, तो क्या और क्यों?

Ans कुछ छात्रों ने अपना घर का काम नहीं किया था। यही कारण है कि उन सभी छात्रों को एक बार वॉलीबॉल कोर्ट के चारों ओर दौड़ने के लिए बनाया गया था। बाद में सभी छात्र सामान्य थे और सपना भी सामान्य था। "

(7) यह प्रश्न संख्या ६ को नोटिस करना और उत्तर देने के लिए भी

यहाँ पर पढ़ना होगा, जो कि के तहत पढ़ा गया है:

"6. क्या आपने प्रिंसिपल को घटना के बारे में सूचित किया है? यदि हाँ, तो क्या उसने अपनी चिकित्सा सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की थी? यदि हाँ, तो क्या?

Ans 24 अगस्त, 1998 को श्री जय काम मलिक स्कूल के प्रभारी थे। उन्हें श्रीमती द्वारा सूचित किया गया था। कैलाश अरोरा कि एक लड़की बेहोश हो गई है और उसने छात्र को चिकित्सा सहायता के लिए श्री नरेश गुप्ता (एमबीबीएस) को भेजा है। मुझे स्टाफ रूम में इस बारे में पता चला। "

(8) एक समान प्रश्नकर्ता भी छात्र को कुमारी सपना को दिया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने 7 सितंबर, 1998 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, चंडीगढ़ को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रारंभिक पूछताछ रिपोर्ट का विषय "दीनिक अखबार, पंजाब केसरी ने 7 सितंबर, 1998 को छात्र को सजा देने के संबंध में दिनांकित किया था," कुमारी सपना "। जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षक ने किसी भी दुश्मनी के कारण छात्र को दंडित नहीं किया था, लेकिन केवल शैक्षिक असाइनमेंट को पूरा नहीं करने के लिए और छात्रों को वॉलीबॉल कोर्ट के आसपास चलने के लिए बनाया गया था और इसके अलावा, छात्रों के माता-पिता, जांच के दौरान कोई बीमार नहीं था- शिक्षक के खिलाफ कोई शिकायत होगी। यह कहा गया है कि 8 सितंबर, 1998 को, पंजाब केसरी ने एक खबर दी जिसमें कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा इस घटना से इनकार किया गया था। इसके अलावा, स्कूल के कर्मचारियों ने भी एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि शिक्षक द्वारा छात्र को कोई सजा नहीं दी गई थी।

(9) प्रतिवादी संख्या 2, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, चंडीगढ़ ने 9 अक्टूबर 1998 को एक आदेश पारित किया जिसके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने के लिए कहा गया। ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन की कॉपी भी याचिकाकर्ता को भेज दी गई थी। 14 अक्टूबर, 1998 को दिनांकित आदेश (अनुलग्नक पी -9) के रूप में पढ़ता है:-

"संदर्भ पत्र संख्या A-II/98/3220 दिनांक 7 सितंबर, 1998, श्रीमती सुनीता रानी, विज्ञान मालकिन, GGS.S. केथल के खिलाफ की गई

जांच। क्योंकि नियुक्ति पत्र आपके कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। उसकी सेवाओं को समाप्त करने के बाद सूचित निदेशालय। "

(१०) इस आदेश के अनुसरण में, जिसमें एक दिशा दी गई थी, स्कूल के प्रिंसिपल, १४ अक्टूबर, १ ९९ (को, वीड ऑर्डर (एनेक्स्योर पी - १०) ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया और उसे आरोप से राहत दी।

(११) अक्टूबर १ ९९ (के महीने में वर्तमान रिट याचिका शुरू की गई थी। इस न्यायालय की एक डिवीजन पीठ, 28 अक्टूबर, 1998 को प्रस्ताव की सूचना जारी करते हुए, के रूप में देखी गई: के रूप में देखा गया:

"यह बताता है कि लगाए गए आदेश ने एक निश्चित कलंक डाला और अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के अनुपालन के बिना सजा के एक उपाय के रूप में पारित किया गया है।
4 जनवरी, 1999 के लिए गति की सूचना। कोई प्रवास नहीं। "

(१२) यह विवादित नहीं है कि तब से याचिकाकर्ता सेवा से बाहर है।

(१३) दायर किए गए लिखित बयान में, राज्य के वकील ने एक स्टैंड लिया है कि याचिकाकर्ता को तदर्थ आधार पर एक स्टॉप-गैप-व्यवस्था के रूप में नियुक्त किया गया था और चूंकि वह सेवा मानदंडों के अनुसार अपने कर्तव्यों को करने में विफल रही थी और खुद को साबित कर दी थी। एक सरकारी नौकर के अनभिज्ञ, उसकी सेवाओं के साथ भेज दिया गया था। यह कहा जाता है कि याचिकाकर्ता ने एक छात्र को कुकरी सपना की पिटाई दी, इतनी निर्दयता से कि वह बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता, के रूप में एक लोक सेवक, अपने कर्तव्यों के प्रति अखंडता और भक्ति बनाए रखने में विफल रहा और उसने एक सभ्य व्यवहार के मानदंडों के खिलाफ काम किया। यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता के संचालन के कारण, शैक्षणिक संस्थान की प्रतिष्ठा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी।

(१४) श्री आर। के। मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कोहल शर्मा, याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित अधिवक्ता, ने सख्ती से तर्क दिया है कि

समाप्ति का आदेश सहज नहीं था, लेकिन अगर आदेश का पदार्थ, परिस्थितियों में भाग लेना और आदेश का आधार हैं। ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट होगा कि एक ही संलग्न कलंक और कथित कदाचार पर आधारित था। यह आग्रह किया गया है कि इस अदालत को घूंघट को उठाना चाहिए और यह जांचना चाहिए कि क्या समाप्ति का आदेश सरल है या कदाचार की जमीन पर पारित किया गया है। इस सबमिशन को मजबूत करने के लिए। रिलायंस को जर्नल सिंह और अन्य बनाम पंजाब और अन्य (अन्य (1) पर रखा गया है।

(१५) श्री इलिमंशु राज। सहायक अधिवक्ता जनरल। हरियाणा ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति नियुक्ति पत्र के अनुसार थी और इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं की जा सकती है। यह कहा गया है कि नियुक्ति पत्र में विशेष रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। राज्य के लिए वकील ने आगे आदेश (एनेक्स्योर पी -10) पर भरोसा किया है कि यह बताने के लिए कि लगाए गए आदेश में कोई कदाचार नहीं है और कोई कलंक नहीं है, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा पारित आदेश (अनुलग्नक पी -10) केवल सेवाओं में कहा गया है कि सेवाएं केवल यह बताती हैं कि सेवाएं बताती हैं याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए। सीखा वकील ने प्रस्तुत किया है कि भले ही आदेश (अनुलग्नक पी - 10) को आदेश के आधार पर पारित किया गया हो (एनेक्स्योर पी - 9), जिसे ऊपर पुन: पेश किया गया है, यह निदेशक के बीच एक आंतरिक संचार था। सार्वजनिक निर्देश और स्कूल के प्रिंसिपल। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया जा सकता है।

(१६) मैंने पार्टियों के लिए वकील द्वारा उन्नत प्रतिद्वंद्वी सबमिशन को अपना विचारशील विचार दिया है। ऊपर दिए गए तथ्यों से। यह उभरता है कि 24 अगस्त, 1998 को, जबकि याचिकाकर्ता कक्षा 10 सेक्शन 'ई' की चौथी अवधि ले रहा था, एक छात्र, अर्थात् कुमारी सपना बेहोश हो गया था। शिक्षक के अनुसार, उसे वॉलीबॉल कोर्ट का एक दौर लेने की सजा दी गई थी। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, उसे कॉर्पोरल सजा दी गई थी)। प्रश्नावली के जवाब में, छात्र कुमारी सपना ने कहा था कि उसने तीन सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन विफल एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए और शिक्षक से अनुरोध किया कि वह

अगले दिन उस प्रश्न का उत्तर देगी। शिक्षक ने स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया था और उसे 2/4 बार चेहरे पर थप्पड़ मारा और धूप में अपना रुख किया और फिर शिक्षक ने उसे 10/15 मिनट के लिए जमीन में दौड़ने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि यह सजा उसे अकेले नहीं बल्कि दस अन्य छात्रों को भी दी गई थी। यह उत्तरदाताओं का भी मामला है कि समाचार आइटम के प्रकाशन के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी को एक प्रारंभिक जांच करने के लिए कहा गया था, जिसमें किसी गवाह की जांच नहीं की गई थी, लेकिन केवल शिक्षक और छात्र को प्रश्नावली दी गई थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद निदेशक सार्वजनिक निर्देशों को भेजा गया था। सीधे आदेश (अनुलग्नक पी -9), जिसे ऊपर पुन: पेश किया गया है। पारित किया गया था और उसी की एक प्रति याचिकाकर्ता को भेजी गई थी। आदेश (अनुलग्नक पी - 9) विशेष रूप से बताता है कि शिक्षक के खिलाफ की गई पूछताछ के कारण, उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था।

(17) नेहरू युवा केंद्र बनाम मेहबूब आलम लास्कर "(2) माननीय के उनके आधिपत्य को शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता की जांच की, जिसमें एक प्रोबेशनर के खिलाफ पारित समाप्ति का आदेश अलग रखा गया था, क्योंकि उसी को प्रकृति में कलंक के रूप में रखा गया था। नेहरू युवा केंद्र सांगथन के मामले (सुप्रा) में, इसके तहत देखा गया था:

"12. एक प्रारंभिक पूछताछ के लिए जो कि कर्मचारी से स्पष्टीकरण कहा जाता है, अगर डिस्चार्ज के एक सहज आदेश के बाद, प्रकृति में दंडात्मक नहीं होने के लिए आयोजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन तब नहीं जब यह कदाचार की खोज पर स्थापित किया जाता है।

13. दीपटी प्रकाश बनर्जी बनाम सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कलकत्ता और अन्य, 1999 (1) एससीटी 861: [(1999) 3 एससीसी 60], इस अदालत ने कहा कि कलंक को कलंकित करने की आवश्यकता नहीं है। केवल समाप्ति क्रम में, लेकिन एक आदेश में भी समाहित किया जा सकता है या समाप्ति या अनुलग्नक के आदेश में निर्दिष्ट कार्यवाही में शामिल हो सकता है।
जब एक अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में नींव होती है, तो यह प्रकृति में कलंक होगा क्योंकि इस तरह

के आदेश के नागरिक परिणाम होंगे।

14. हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में फैसलों पर विचार करें क्योंकि इस न्यायालय ने हाल ही में जसवंतसिंह प्रतापसिंह जडेजा बनाम Rjkot नगर निगम और ANR में इस न्यायालय के रूप में काम किया है। [(२०० [) १२ स्केल ११५) ने कुछ लंबाई पर प्रश्न पर विचार किया है। हालांकि, रिलायंस को श्री राणा रणजीत सिंह ने अभिजीत गुप्ता बनाम एस.एन.बी. राष्ट्रीय केंद्र, बुनियादी विज्ञान और अन्य [(2006) 4 एससीसी 469]। उक्त निर्णय को जेदेजा (सुप्रा) में ध्यान में रखा गया है, जिसमें कहा गया है:

'यदि नियोक्ता की संतुष्टि ने अपीलकर्ता की ओर से असंतोषजनक प्रदर्शन पर आराम किया, तो मामला अलग हो सकता है, लेकिन उस मामले में, लगाए गए आदेश से यह स्पष्ट है कि यह उसके प्रदर्शन की असंतोषजनक प्रकृति और चरित्र नहीं था केवल जिसे ध्यान में रखा गया था, लेकिन उनके कृत्यों की श्रृंखला के रूप में अच्छी तरह से, उनके हिस्से पर कदाचार को भी ध्यान में रखा गया था। यह कहना एक बात है कि वह नौकरी के लिए अनुपयुक्त पाया गया था, लेकिन यह कहना एक और बात है कि कहा गया था कि उसने कुछ कदाचार किया है। '

जैसा कि तत्काल मामले में, अब यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी की सेवाओं को कदाचार की खोज पर समाप्त कर दिया गया था, अभिजीत गुप्ता (सुप्रा) में इस अदालत के उक्त निर्णय का कोई आवेदन नहीं है।

15. रिलायंस को जय सिंह बनाम भारत के संघ और अन्य, 2006 (4) एससीटी 66: [(2006) 9 एससीसी 717) पर भी रखा गया है। उस मामले में, अपीलकर्ता के आचरण को रिकॉर्ड में "असंतोषजनक" के रूप में दिखाया गया था।

उसमें, इस अदालत ने देखा कि समाप्ति का आदेश एकमात्र मकसद था न कि उस नींव के लिए:

'9। यह सवाल कि क्या सेवा की समाप्ति सरल है या कई मामलों में दंडात्मक की जांच की गई है, उदा। धनंजय बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और मैथ्यू पी। थॉमस बनाम केरल राज्य

नागरिक आपूर्ति कॉर्प। लिमिटेड प्रोबेशन की अवधि के दौरान पारित समाप्ति सरलीटर का एक आदेश अनियंत्रित बहस पैदा कर रहा है। हाल के दो इस न्यायालय के दिष्टी प्रकाश बेनरजी बनाम सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और पवनेंद्र नारायण वर्मा बनाम मेडिकल साइंसेज बनाम पवनेंद्र नारायण वर्मा के फैसले से पहले के अधिकांश फैसलों के सर्वेक्षण के बाद यह देखा जा सकता है कि जब समाप्ति के आदेश का इलाज किया जा सकता है। सरलीकृत के रूप में और जब इसे दंडात्मक के रूप में माना जा सकता है और जब एक कलंक को परिवीक्षा की अवधि के दौरान डिस्चार्ज किए गए कर्मचारी से जुड़ा होने के लिए कहा जाता है। दोनों ओर से सीखे हुए वकील ने इन निर्णयों पर या तो अपने संबंधित सामग्री के समर्थन में या वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए बताए गए सिद्धांतों के आवेदन के उद्देश्य के लिए उन्हें अलग करने के लिए संदर्भित किया। दीपटी प्रकाश बनर्जी में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद यह संकेत दिया गया था कि जब समाप्ति के एक साधारण आदेश को कदाचार के आरोपों पर 'स्थापित' के रूप में माना जाता है और जब शिकायतें केवल समाप्ति के इस तरह के एक सरल आदेश को पारित करने के लिए एक मकसद के रूप में हो सकती हैं। । उक्त फैसले के पैरा 21 में एक अंतर इस प्रकार समझाया गया है: (SCC पीपी। 71-72)

'21। यदि निष्कर्षों को एक जांच में कदाचार के रूप में, अधिकारी की पीठ के पीछे या नियमित विभागीय जांच के बिना, समाप्ति के सरल आदेश को आरोपों पर 'स्थापित' के रूप में माना जाना है और बुरा होगा। लेकिन अगर जांच नहीं की गई थी, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया था और नियोक्ता को जांच करने के लिए इच्छुक नहीं था, लेकिन साथ ही, वह उस कर्मचारी को जारी नहीं रखना चाहता था जिसके खिलाफ शिकायतें थीं, यह केवल एक मामला होगा मकसद और आदेश बुरा नहीं होगा। इसी तरह की स्थिति है यदि नियोक्ता नियमित विभागीय कार्यवाही में देरी के कारण आरोपों की सच्चाई के बारे में पूछताछ नहीं करना चाहता था या वह पर्याप्त सबूत हासिल करने के बारे में संदिग्ध था। ऐसी परिस्थिति में, आरोप एक मकसद होगा न कि नींव और समाप्ति का सरल आदेश मान्य होगा। '

निर्णयों की एक लंबी कतार से यह हमें प्रतीत होता है कि क्या समाप्ति का एक आदेश सरल है या दंडात्मक अंततः प्रत्येक मामले के तथ्यों

और परिस्थितियों के संबंध में होने का निर्णय लिया गया है। कई बार नींव और मकसद के बीच का अंतर समाप्ति के एक क्रम के संबंध में या तो पतला है या अतिव्यापी। या तो एक या दूसरी श्रेणी में गिरने वाली समाप्ति के सादगी के आदेशों को वर्गीकृत करना या वर्गीकृत करना मुश्किल हो सकता है, कदाचार के आधार पर समाप्ति के आदेश को पारित करने के लिए नींव के रूप में या सेवा में जारी रखने के लिए अनपेक्षितता के आधार पर मकसद पर। " मूल में)

(18) यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि यह अखबार में रिपोर्ट के प्रकाशन के कारण था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ और उसके बाद, उस जांच के आधार पर प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी। उसकी सेवाओं के साथ भेज दिया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता की सेवाओं को उसके हिस्से पर असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण नहीं किया गया है, लेकिन ओवरट कृत्यों के कारण, जो कदाचार की राशि है। अगर ऐसा है। नियोक्ता के लिए याचिकाकर्ता को सुनने का अवसर देना अनिवार्य था। इसलिए, याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति का क्रम (अनुलग्नक पी -10) सहज लग सकता है, लेकिन इसके प्रभाव और पदार्थ के लिए समान, प्रकृति में कलंक है। आदेश (अनुलग्नक P-10) आदेश के अनुपालन में पारित किया गया था (अनुलग्नक P-9)। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को यह दिखाने के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए कि क्या उसने छात्र पर कथित सजा दी है या नहीं।

(19) इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए उपरोक्त दृश्य को माननीय के हालिया फैसले से भी समर्थन मिला, जो कि पंजाब राज्य और अन्य बनाम कांस्टेबल अवतार सिंह (मृत) के माध्यम से LRS (३) में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह है, जिसमें यह है। के तहत आयोजित किया गया है:

"13 हमने पार्टियों के लिए सीखा वकील सुना है। हम पंजाब राज्य के लिए सीखे हुए वकील को प्रस्तुत करने के साथ कुल समझौते में हैं कि इस मामले में शामिल विवाद अब पूर्णांक नहीं है। पृथ्वीपल सिंह बनाम पंजाब एंड अन्य, 2001 (1) एससीटी 459: (2002) 10 एससीसी 133 में इस अदालत के दो-न्यायाधीश बेंच के फैसले पर ध्यान दें। अदालत ने कहा कि एक बार कलंक है, सिद्धांत अच्छी तरह से बसा

हुआ है, किसी भी आदेश को पारित करने से पहले एक अवसर दिया जाना चाहिए। यहां तक कि जहां डिस्चार्ज का एक आदेश सहज दिखता है, लेकिन एक करीबी जांच पर, पर्दे के पीछे देखकर अगर कोई सामग्री कदाचार की मौजूद है और जो डिस्चार्ज के आदेश को पारित करने की नींव है, या इस तरह के यथोचित अनुमान लगाया जा सकता है, तो यह संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है कि कोई भी परिणामी आदेश, यहां तक कि डिस्चार्ज की, कलंक के रूप में माना जाएगा। सुखविंदर सिंह (सुप्रा) में निर्णय तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था और 2005 में उस फैसले के मद्देनजर, इस अदालत के लिए एक अलग दृष्टिकोण लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम उक्त फैसले से बाध्य हैं। ”

(२०) ऊपर किए गए डिकुस्सियन के मद्देनजर, इस अदालत की राय है कि इस मामले में एक नियमित जांच की जानी चाहिए थी और याचिकाकर्ता, एक तदर्थ कर्मचारी, को खुद का बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

(२१) इसलिए, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति है और लागू आदेशों (अनुलग्नक पी -9 और पी -10) को इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को सेवा और संबंधित अधिकारियों में बहाल किया जाएगा, यदि ऐसा है, तो सलाह दी जाएगी, कानून के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ नई कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्रता पर होगी। हालाँकि, याचिकाकर्ता किसी भी बैक मजदूरी का हकदार नहीं होगा।

(२२) हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ

सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पIरिंदर सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा